भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2553
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- दलहन और तिलहन का उत्पादन

2553. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में दलह्न और तिलहन का कुल उत्पादन कितना है और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कितनी खरीद की गई है;

(ख) इसी अवधि के दौरान आयातित दलहन और खाद्य तेलों की कुल मात्रा और मूल्य, वर्ष-वार कितना है;

(ग) भारत के दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी दलहन के निरंतर उच्च आयात के क्या कारण हैं; और

(घ) दलह्न और तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान देश में दलहन और तिलहन के कुल उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

फसल	उत्पादन लाख टन में				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
दलहन	254.63	273.02	260.58	242.46	256.83
तिलहन	359.46	379.63	413.55	396.69	429.89

विगत 5 वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी गई दलहन और तिलहन का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान आयातित दलहन और खाद्य तेलों की मात्रा और मूल्य का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): विगत 5 वर्षों में देश में दलहन के उत्पादन में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

दलहन मिशन का उद्देश्य तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देना, दलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना और फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शामिल है। यह मिशन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के मानदंडों के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा तूर, उड़द और मसूर की सुनिश्चित खरीद का भी समर्थन करता है। इस मिशन के तहत वर्ष 2030-31 के अंत तक 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता के साथ 350 लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कानपुर स्थित आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और भोपाल, धारवाड़, बीकानेर और खोर्दा स्थित अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों में दलहन फसलों पर कार्यनीतिक अनुसंधान कर रही है। साथ ही, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से खरीफ और रबी दलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से व्यावहारिक अनुसंधान भी कर रही है, जिसका उद्देश्य दलहन की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थान-विशिष्ट उच्च उपज वाली किस्मों और उसके अनुरूप उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार करना है।

घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को अनुमोदन प्रदान किया। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030-31 तक प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को 33 मिलियन हेक्टेयर तक विस्तारित करना और उत्पादकता में 2,112 किलोग्राम/हेक्टेयर तक सुधार करना है। यह मिशन बाजार संपर्क के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण से कार्यान्वित किया जा रहा है। मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का प्रबंधन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों जैसे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाता है। इन क्लस्टरों के तहत, किसानों को 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए निशुल्क उच्च गुणवत्ता वाले बीज और बेहतर कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह मिशन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से तेल पुनर्प्राप्ति में सुधार के लिए फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर (ऑयल मिल) की स्थापना और उन्नयन को भी सहायता प्रदान करता है। यह मिशन फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन (एफएलडी), क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन (सीएफएलडी) और ब्लॉक-लेवल डेमोंस्ट्रेशन (बीएलडी) के माध्यम से तिलहन फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है ताकि किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाने और आवश्यक इनपुट तक पहुंचने में सहायता मिल सके।

यह मिशन केंद्रीय बीज पोर्टल (साथी) पर बीज रोलिंग योजना का उपयोग करके ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करके प्रमाणित बीजों की उपलब्धता को सुदृढ़ बनाता है। यह मिशन उत्पादन और भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में नए सीड-हब और बीज भंडारण इकाइयों की स्थापना को सहायता प्रदान करता है।

अनुबंध-I

पीएसएस के तहत दलहन और तिलहनों की खरीद का विवरण

वर्ष	खरीदी गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	
	तिलहन	दलहन
2020-21	2,95,212.34	8,17,046.85
2021-22	1,51,634.73	30,30,956.91
2022-23	11,70,656.63	28,31,401.10
2023-24	14,41,356.22	6,93,769.32
2024-25	44,13,059.41	18,39,504.77

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अनुबंध- II

दलहन और खाद्य तेलों (वनस्पति तेलों) का आयात

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

वर्ष	दलहन		खाद्य तेल (वनस्पति तेल)	
	पीसी कोड- A7		पीसी कोड- B8	
	मात्रा ('000 मीट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये करोड़ में)	मात्रा ('000 मीट्रिक टन में	मूल्य (रुपये करोड़ में)
2020-21	2466.16	11937.59	13540.01	82123.26
2021-22	2699.69	16627.58	14278.16	141531.78
2022-23	2496.17	15780.56	15745.14	167269.99
2023-24	4738.90	31071.63	15520.48	123078.72
2024-25	7255.59	46427.60	16409.66	146449.67

*****